शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार
प्रकाशन का 48 वां वर्ष
ई-पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 48 अंक-8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20-27 फरवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

जुएं निकालने की जगह सिर ही काट देने से नहीं बदलेगी व्यवस्था सुक्खु और जयराम हुए आमने-सामने

- अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग भंग करने से उठी चर्चा
- चिट्टों पर भर्तियों का प्रकरण सामने आने पर गठित हुआ था हमीरपुर बोर्ड
- हर्ष गुप्ता और अवय शुक्ला जांच कमेटियों की रिपोर्टों पर कितने दंडित हो पाये हैं आज तक सामने नहीं आया है
- आऊटसोर्स केवल कमीशन का साधन बनकर रह गया है
- 94 कंपनियों को मिले 23 करोड़ से उठी चर्चा
- क्या अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग की जांच का अन्तिम परिणाम इसी सरकार के कार्यकाल में आ पायेगा
- जब कर्मचारी भर्तीयों से जुड़ा हर अदारा सवालों में है तो नौकरियों के अभ्यर्थी कहां जायें?
- क्या सरकार भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर करेगी?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने हमीरपुर स्थित अधीनस्थ कर्मचारी सेवाएं चयन आयोग को भंग कर दिया। यह कदम तब उठाया गया जब जे.ओ.ए. (आई.टी) की परीक्षा का पेपर लीक होने की शिकायत परीक्षा होने से पहले ही एक अभ्यर्थी के माध्यम से विजिलैन्स के पास पहुंच गयी। शिकायत मिलने पर पूरा तन्त्र हरकत में आ गया। परीक्षा रद्द कर दी गयी। कारवाई में कुछ लोगों को गिरफ्तारीयां हुई हैं। इसी कारवाई के बीच यह आशंकाएं उभरी कि कहीं पूर्व में हुई परीक्षाओं में भी ऐसा ही न हुआ हो। इसी आशंका पर आयोग निलंबित कर दिया गया और जांच के लिए एस.आई.टी. का गठन कर दिया गया। सचिव शिक्षा को भी जांच करके रिपोर्ट देने के आदेश दिये गये। यह सूचनाएं सामने आयी की अठारह कोड की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। विजिलैन्स की कोई रिपोर्ट अभी तक अधिकारिक रूप से सामने नहीं आयी है। न ही शिक्षा सचिव की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। लेकिन इन्हीं रिपोर्टों के बीच आयोग को ही भंग कर दिया गया है। आयोग को भंग करने पर मुख्यमंत्री का ब्यान आया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इसमें ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त था। मुख्यमंत्री के ब्यान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मांग की है कि इस भ्रष्टाचार में व्याप्त सबके नाम उजागर किये जायें और उनके खिलाफ कारवाई की जाये। इसी प्रतिक्रिया के साथ जयराम ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कारवाई केवल भाजपा द्वारा लगाये गये अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिये की गयी है। जयराम की प्रतिक्रिया और आरोपों के परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार एक तय समय सीमा के भीतर सारे प्रकरण को अदालत पहुंचा कर दोषियों को दण्डित करवाये।

स्मरणीय है कि एक समय प्रदेश में चिट्टों के माध्यम से हर विभाग और सरकारी उपक्रमों में हजारों की संख्या में भर्तियां होने का मामला सामने आया था। इन भर्तीयों की जांच के लिये हर्ष गुप्ता और अवय शुक्ला दो कमेटियां गठित हुई थी। इन कमेटियों की रिपोर्टों पर प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच की मांग की गयी थी। उच्च न्यायालय ने भी रिपोर्टों का कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिये थे। लेकिन आज तक यह सामने नहीं आ पाया है कि इस प्रकरण में कौन-कौन दण्डित हुआ है। इसी परिदृश्य में भविष्य में ऐसा न हो और एक अलग संस्था सरकारी नौकरियों में भर्ती का काम देखे। इस उद्देश्य के लिये हमीरपुर में इस संस्थान का गठन हुआ था। यहां भी पेपर लीक की शिकायतें पहली बार आयी हैं। इन शिकायतों के परिदृश्य में संस्थान को ही भंग कर देने के फैसले को सिर से जुएं निकालने की बजाये सिर को ही काट देने के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि प्रदेश में नौकरियां देने वाला सरकार से बड़ा कोई अदारा नहीं है। इस आयोग के पास इस समय करीब चार हजार भर्तीयां करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही थी। अब यह काम प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया गया है। लोक सेवा आयोग में 2018 जनवरी में सदस्यों के दो पद सृजित करके एक भर लिया गया था लेकिन आगे चलकर जो जो सदस्य सेवानिवृत्त होते गये उनके स्थान पर नई नियुक्तियां तत्काल नहीं हो पायी और एक समय यह स्थिति बन गयी कि आयोग में एक ही सदस्य रह गया। लेकिन इसी दौरान भर्तीयों को लेकर जो हुआ यदि उस पर नजर डाली जाये तो यह सामने आता है कि 2018 से लेकर 2022 तक भर्तीयों के जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उनके मुताबिक करीब दो सौ विज्ञापन जारी हुए हैं। जिनमें 2018 में 18, 2019 में 25, 2020 में 12, 2021 में 62 और 2022 में 64 विज्ञापन जारी हुए हैं। 2022 चुनावी वर्ष था और इसमें 64 विज्ञापन जारी हुए। जबकि 2017 भी चुनावी वर्ष था और उसमें 17 विज्ञापन जारी हुए थे। 2021 और 2022 में जब आयोग में सदस्यों के कुछ पद खाली चल रहे थे तब आयोग में इतने विज्ञापनों की अनुपालना कैसे हो पायी होगी यह विचार का विषय है। कई भर्तीयों की प्रक्रिया तो शायद एक एक वर्ष में भी पूरी नहीं हो पायी है। ऐसे में अधीनस्थ सेवाएं चयन का काम भी अब लोक सेवा आयोग को देना अपने में ही सवाल खड़े कर जाता है। यह आंकड़े आयोग की साइट पर उपलब्ध हैं।

अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के बाद भर्तीयों का तीसरा बड़ा माध्यम आऊटसोर्सिंग है। आऊटसोर्स कमीशन खाने का एक बड़ा उद्योग बन कर रह गया है। जयराम सरकार के समय रमेश धवाला, होशियार सिंह, राजेंद्र राणा और विक्रमादित्य ने सवाल पूछा था कि तीन वर्षों में सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने जवाब में कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मोहनलाल बरागटा, मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य ने सवाल पूछा था कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में कितने लोगों को आऊटसोर्स के माध्यम से नौकरी पर रखा गया। इसमें 12165 का आंकड़ा दिया गया और कहा गया कि पिछले वर्ष 3000 लोगों को रखा गया था। इन लोगों के लिये 94 कंपनीयों को 23, 09,58,224 रुपए का कमीशन दिया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि आऊटसोर्स कमीशन खाने का ही माध्यम बनकर रह गया है। फिर आऊटसोर्स कंपनियों को उनके माध्यम से लगे कर्मचारियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपनियां किस आधार पर कर्मचारीयों का चयन करती है यह स्पष्ट नहीं है। क्योंकि वह अपने कमीशन तक ही सीमित रहते हैं। इस तरह कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार से लेकर आऊटसोर्स तक हर माध्यम की विश्वसनीयता प्रश्नित हो चुकी है। आज जब कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया है तब यह सवाल बड़ा बन गया है कि एक विश्वसनीय तन्त्र की स्थापना कैसे हो पायेगी? क्योंकि हर सरकार के समय चयन की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। सरकार जांच आदेशित कर देती है जिसका अन्तिम फैसला आते-आते कई सरकारें बदल जाती हैं। इसलिये सुक्खु सरकार को अपनी व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता पर अमल करने के लिये सिर से जुएं निकालने का प्रयास करना होगा न कि सिर ही काटने का।

गणतंत्र दिवस परेड के एनसीसी प्रतिभागी दल ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में भाग लेने वाले एनसीसी दल के हिमाचल प्रदेश के सदस्यों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री रैली में भी भाग लिया था। राज्यपाल ने परेड में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए इन प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया।

इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के 14 एनसीसी प्रतिनिधियों ने आरडी कैंप में भाग लिया, जिसमें 7 लड़के और 7 लड़कियां शामिल थीं। इनमें हिमाचल प्रदेश की कैडेट मनिका सेठी ने मास्टर सेरेमनी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार अन्य प्रतियोगिताओं में भी इन कैडेटों का शानदार प्रदर्शन रहा।

राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कैडेटों ने राज्यपाल के साथ दिल्ली में आयोजित एक माह के शिविर और पंजाब के रोपड़ में आयोजित एक माह के शिविर के अपने अनुभव साझा किए।

राज्यपाल ने दल के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि समारोह में राज्य के 14 कैडेटों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में शामिल होने के लिए सदैव उत्साहित रहते हैं। यह उत्साह इन कैडेटों में भी देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इन युवाओं में उन्हें आज का भारत दिख रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर को विस्तारित करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें माध्यम से छात्र कर्तव्य परायणता और अनुशासन सीखते हैं जो उनके पूरे जीवन भर काम आता है।

राज्यपाल ने उनका आहवान किया कि वे अपने भविष्य में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहें। उन्होंने कहा कि युवाओं के विकास में एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने यह भी कहा कि एनसीसी एक भारतीय होने की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने एनसीसी कैडेटों के भविष्य के सभी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।

इससे पूर्व, अतिरिक्त महानिदेशक, एनसीसी निदेशालय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तथा चंडीगढ़ मेजर जनरल के. विनोद ने राज्यपाल का आभार व्यक्त दिया और उनसे मंडी जिले में एनसीसी प्रशिक्षण के लिए भवन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने के संबंध में आग्रह किया।

इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा, एनसीसी निदेशालय और और राजभवन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने की सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सैनिक बोर्ड और राज्य प्रबंधन समिति के पुनर्गठन की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएं ताकि पूर्व सैनिकों से संबंधित मामलों और उनकी शिकायतों का समय पर निस्तारण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों, सैनिकों की युद्ध विधवाओं, विश्वयुद्ध के योद्धाओं, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों और सेवारत सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास और कल्याण एवं देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि आम जनता को सशस्त्र बलों के बारे में जानकारी प्रदान करने और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवाएं देने के लिए प्रेरित करने की दिशा में विभाग को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका लाभ पूर्व सैनिकों को मिल रहा है।

हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने विभाग के कार्यों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

एसजेवीएन ने 75 मेधावी छात्रों को सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की

शिमला/शैल। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन नन्द लाल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के 75 मेधावी छात्रों को एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की। इस समारोह के मुख्य अतिथि नन्द लाल शर्मा ने एसजेवीएन कारपोरेट मुख्यालय, शिमला में आयोजित एक अवार्ड समारोह में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों में से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 24,000/- रुपए की स्कॉलरशिप के चेक प्रदान किए।

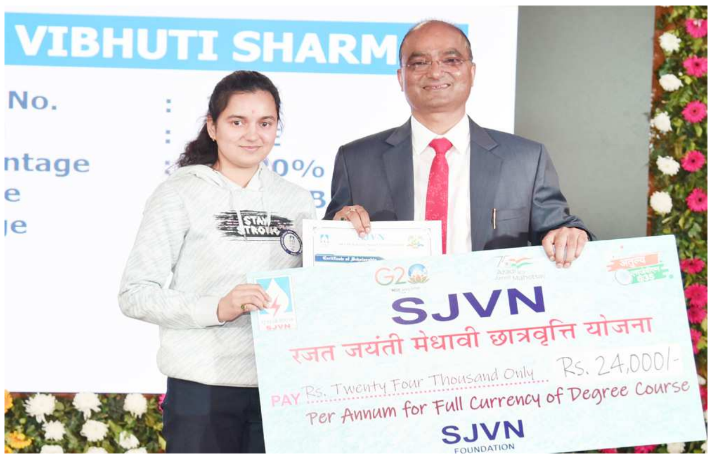
VIBHUTI SHARM
No.
ntage
e
ie
SJVN
रजत जयंती मेधावी छात्रवृत्ति योजना
PAY Rs. Twenty Four Thousand Only
Rs. 24,000/-
Per Annum for Full Currency of Degree Course
SJVN
FOUNDATION

नन्द लाल शर्मा ने छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि और स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए बधाई दी, जो उन्हें अपनी पसंद की विधाओं में उच्चत्तर शिक्षा हासिल करने में सहायक होगी। शर्मा ने कहा कि सीबीएसई, आईसीएसई और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के राज्य शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों से 12वीं कक्षा के 100 मेधावी छात्रों का चयन किया गया है। एसजेवीएन शहरी, ग्रामीण और राज्यों के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के 75 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड और बिहार में एसजेवीएन की परियोजनाएं भी मेधावी स्कॉलरशिप प्रदान कर रही हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश की 55 छात्राओं के साथ 70 छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गयी है। वर्ष 2012 में योजना आरंभ होने के पश्चात से यह छात्राओं द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वाधिक स्कॉलरशिप है।

एसजेवीएन में हम शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं। हमारी मेरिट स्कॉलरशिप योजना छात्राओं को उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं को साकार करने और देश का उज्जवल भविष्य बनने में सहायता कर रही है।

नन्द लाल शर्मा ने आगे बताया कि एसजेवीएन ने इस योजना के तहत अब तक 1894 मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान की हैं। इनमें से 1188 विद्यार्थियों ने अपना पाठयक्रम पूरा कर लिया है और शेष विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज, विधि विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों आदि में व्यावसायिक डिग्रीयां और डिप्लोमा का पाठयक्रम कर रहे हैं।

इस अवसर पर गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक), सुशील शर्मा, निदेशक (विद्युत), प्रेम प्रकाश, मुख्य सतर्कता अधिकारी और एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एसजेवीएन अपनी सीएसआर और सततशील पहलों को अपने पंजीकृत ट्रस्ट 'एसजेवीएन फाउंडेशन' के माध्यम से कार्यान्वित करता है। एसजेवीएन सिल्वर जुबली मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम को वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था। चयनित छात्रों को उनके पाठयक्रम के पूरा होने तक 2,000 रुपए प्रतिमाह की स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाता है। परियोजना से संबद्ध परिवारों, संबद्ध क्षेत्रों और संबद्ध जिलों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं।

एसजेवीएन फाउंडेशन छह शीर्षो नामत: स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, संरचनात्मक एवं सामुदायिक विकास, सततशील विकास, स्थानीय संस्कृति, विरासत एवं खेल का संरक्षण एवं संवर्धन, प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं के दौरान सहायता के तहत विभिन्न पहलें कार्यान्वित करता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी दी। राज्यपाल ने राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद व्यक्त की कि राज्य पुलिस देवभूमि को अपराधमुक्त करने के लिए सख्ती से कार्य करेगी।

संजय कुण्डू ने अवगत करवाया कि प्रदेश के भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा विस्तृत कार्ययोजना के तहत कदम उठाए हैं और इन क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी। राज्य पुलिस नशे और नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों के निवारण के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कारवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों से सख्ती से निपटा जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा के बारे में यातायात पुलिस के माध्यम से कई उपाय सुनिश्चित किए गए हैं ताकि लोगों के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस संगठित अपराधों मुख्य रूप से अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कारवाई कर रही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिदेशक के साथ हुई एक बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय ड्रग तस्करों, गैंगस्टरों और अपराधियों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए दोनों राज्यों की पुलिस अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्यपाल का मार्गदर्शन राज्य पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण तथा विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाने आवश्यक हैं। इससे जहां राज्य में पर्यटकों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं स्थानीय निवासियों को आपातकालीन स्थिति में शीघ्र सहायता उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हेलीपोर्ट निर्माण के लिए लंबित आवश्यक वन स्वीकृतियों के विषय में अविलंब निर्णय लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पूर्ण रूप से ई-वाहन अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए प्रदेश के सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर निर्मित किए जाने हैं। उन्होंने आग्रह किया कि इन कार्यों में गति लाने के लिए वन भूमि के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां समय पर प्रदान की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कुछ जगह पर वन स्वीकृतियों में विलम्ब के कारण स्कूल भवन निर्माण इत्यादि के कार्य में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने आग्रह किया कि इन मामलों में स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जाएं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के वन अधिकारी वन अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम सहित अन्य विषयों पर केंद्रीय स्तर पर और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें ताकि स्वीकृतियां समय पर प्राप्त हो सकें।

उन्होंने प्रदेश के जल अभ्यारण्यों एवं इको टूरिज्म दिशा निर्देशों के संबंध में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया।

बैठक में परिवेश पोर्टल, नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम, स्कूल नर्सरी योजना, नगर वन योजना, राज्य में गर्मियों के मौसम में दावानल सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया।

केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

बैठक में केंद्रीय वन सचिव लीना नंदन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में बंजर पहाड़ियों के वनीकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा पौधरोपण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिप्पा में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) की शासी निकाय की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश कैम्पा के अन्तर्गत प्रदेश के बंजर वन क्षेत्रों के वनीकरण के लिए नई पहल की जाएगी।

उन्होंने कहा कि छोटे क्षेत्रों के पौधरोपण के बजाय बंजर पहाड़ियों के वनीकरण के लिए बड़े क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से पौधरोपण किया जाएगा। जलवायु परिस्थितियों के अनुसार पौधे रोपित किए जाएंगे और इस कार्य के लिए समर्पित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा जो जिम्मेदार और जवाबदेह तरीके से इनके संरक्षण का कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हरित राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बंजर वन भूमि के वनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 12 जिलों में 256 हैक्टेयर से अधिक बंजर वन भूमि क्षेत्र को चिन्हित किया गया है तथा 5 वर्षों के दौरान यहां रोपित पौधों का उचित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य के लिए 8.83 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इस अभियान में क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि इसे जन अभियान बनाया जा सके। उन्होंने पौधरोपण के उपरांत इसकी समुचित निगरानी करने तथा संबंधित उपमंडलाधिकारियों को निगरानी प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रदेश के प्रत्येक वन मंडल में एक मॉडल नर्सरी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी 45 नर्सरियों में केंचुआ खाद इकाई, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, स्प्रिंकलर, रूट ट्रेनर्स और टिशू कल्चर लैब इत्यादि की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नर्सरी की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। नर्सरी तैयार करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और यह देशभर में किए जा रहे नवीन कार्यों को साझा करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र साबित होंगे। यह मॉडल नर्सरी प्रदेश की वन्य संपदा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विस्तार केन्द्रों के रूप में भी कार्य करेंगी।

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

मुख्य सचिव ने सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। प्रदेश में शरद ऋतु में औसतन कम बर्फबारी व वर्षा के कारण भविष्य में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रदेश में सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

उन्होंने जल शक्ति विभाग को सभी पेयजल योजनाओं से सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल के प्राकृतिक स्त्रोतों के रखरखाव तथा इनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने वन विभाग को सूखे की स्थिति के कारण संभावित दावानल संबंधी घटनाओं रोकने के लिए समुचित उपाय करने तथा पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए पर्याप्त चारा व पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने सभी उपायुक्तों को इस संबंध में समन्वय बैठक आयोजित करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से पेयजल का सदुपयोग सुनिश्चित करने का आहवान भी किया।

बैठक में उपायुक्तों तथा संबंधित विभागाध्यक्षों से इस संबंध में विभिन्न तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

बैठक में प्रधान सचिव राजस्व एवं वन, सचिव जलशक्ति एवं बागवानी, सचिव कृषि एवं पशुपालन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्त बैठक में वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से शामिल हुए।

हिमाचल प्रदेश में 5जी से होगी प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में राज्य के लिए 5जी सेवा शुरू की। प्रदेश सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को तीव्र गति से अविलंब, निर्बाध और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली उपलब्ध करना चाहती है।

प्रदेश में 5जी तकनीक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा प्रदान करेगी। सभी अत्याधुनिक 5जी सेवाएं विभिन्न प्रकार के सेंसर और उपकरणों के माध्यम से लोगों को संचार के अत्याधुनिक अनुभवों से परिचित कराएगी। विनिर्माण क्षेत्र में 5जी के उपयोग से लागत कम होगी और उत्पादकता में सुधार होगा। इस सेवा से लॉजिस्टिक लागत वर्तमान के लगभग 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

इस सेवा का सुरक्षा और निगरानी क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

इस तकनीक के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राहत उपलब्ध करवाना और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एचडी कैमरों से लाइव 4के फीड की सुविधा मिलेगी। यह जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन जैसे गहरी खदानों, अपतटीय गतिविधियों आदि में लोगों की भूमिका को कम करने में भी सहायता करेगा।

यह तकनीक देश भर के दूरस्थ क्षेत्रों में निर्बाध कवरेज प्रदान करेगी। यह ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगा। 5जी सेवाओं के विस्तार से राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा। राज्य सरकार की प्रमुख परियोजनाओं जैसे पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बागवानी, कृषि, शिक्षा आदि क्षेत्रों को भी विस्तार प्रदान करने में 5जी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नवीनतम पाठयक्रम शुरू किए जाएंगे। ताकि इन क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

जाइका के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के प्रयास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय सहायता के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) का सहयोग लेने पर विचार कर रही है। इस पहल के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय 2835 करोड़ रुपये है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए 1620 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है जिसमें 1010 करोड़ रुपये के अपेक्षित वित्तीय परिव्यय से हमीरपुर, चंबा और नाहन में नए चिकित्सा महाविद्यालयों को सुदृढ़ करना शामिल है। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में कैंसर से संबंधित सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने पर 400 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। सरकार नर्सिंग शैक्षणिक ढांचा और नए चिकित्सा महाविद्यालयों में हाई-एंड डायग्नोस्टिक क्षमता के लिए 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि के लिए जाइका से विचार-विमर्श कर रही है।

प्रदेश में द्वि-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार जाइका के वित्तपोषण से 1215 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव कर रही है। इसमें प्रत्येक चिकित्सा खंड में नागरिक अस्पतालों में द्वि-स्तरीय देखभाल सुविधा जैसे सीटी स्कैन व आधारभूत ढांचे के लिए 988 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सेकंडरी केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 135 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं तथा 92 करोड़ रुपये अन्य नागरिक अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव और डायग्नोस्टिक्स, पावर बैकअप और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेशवासियों को उनके घर-द्वार के निकट विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है और इस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए धन का अभाव आड़े नहीं आएगा।

स्वास्थ्य विभाग इन योजनाओं के आधार पर एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस पर जाइका के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी।

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बड़े, बुद्धि का विकास होऔर मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। – स्वामी विवेकानंद–

सम्पादकीय

क्या छापेमारी और गिरफ्तारी से कांग्रेस का बढ़ना रोक पाएंगे मोदी

अदानी प्रकरण से विश्व का शेयर बाजार भी हिल गया है। विदेशी निवेशकों ने इसमें से अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। विदेशी बैंकों ने अदानी समूह के शेयरों पर कर्ज देना बन्द कर दिया । जो व्यक्ति अमीरों की सूची में 609 वें स्थान से उठकर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था वह अब हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शायद 27 वें पायदान पर आ पहुंचा है। देश के हर बड़े सार्वजनिक प्रतिष्ठान का प्रबन्धन अदानी समूह के पास कैसे पहुंचा जो देश का नम्बर एक और विश्व का दूसरा बड़ा अमीर हो लेकिन टैक्स अदा करने वाले पहले पन्द्रह की सूची में भी न हो तो ऐसे करिश्मे को लेकर सवाल उठना स्वभाविक है। यह सवाल संसद के पटल पर आ चुके हैं। इन सवालों का जवाब देश की सरकार और देश की निगरान एजेन्सीयों से पूछा जाना है। संसद के अन्दर यह काम विपक्ष को करना है और बाहर मीडिया को करना है। जो लोग हिन्डनवर्ग की रिपोर्ट को देश और अदानी पर हमला करार दे रहे हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाना चाहिये कि क्या देश के बैंकों और एलआईसी जैसी संस्थाओं के पास आम आदमी का पैसा जमा नही है? आम आदमी के इस जमा पर ब्याज दरें क्यों कम हुई हैं? जीरो बैलेन्स के नाम पर खोलें खातों पर न्यूनतम जमा की शर्त क्यों लगानी पड़ी। बैंक की सेवाएं फीस के दायरे में क्यों आ गयी? नोटबन्दी के रियल एस्टेट और ऑटोमोबाईल क्षेत्रों को आर्थिक पैकेज क्यों दिये गये? क्या वह पैसा वापस आ गया है? मोदी सरकार ने जितना सहयोग अदानी समूह को दिया है ऐसा ही सहयोग और कितने घरानों को मिला है। जब देश बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है तो प्रति व्यक्ति कर्ज क्यों बढ़ रहा है? महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। हर चुनाव में नये ही नारे क्यों उछालने पड़ रहे हैं पूरानों का हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता।

ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो आज हर आदमी के जहन में कौंध रहे हैं क्योंकि वह इनका भुक्त भोगी है। उसकी विडणबना यही है कि वह स्वयं व्यवस्था से सवाल नही पूछ पाता। वह उम्मीद करता है कि मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व यह सवाल पूछे। आज मीडिया का एक बड़ा वर्ग यह सवाल पूछने का साहस नहीं कर रहा है और इसलिये गोदी मीडिया के संबोधन से संबोधित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं। भले ही उनके खिलाफ देशद्रोह और अन्य तरह के मामले बनाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं की भी यही स्थिति चल रही है। जो सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच एजेन्सीयों की छापेमारी हो रही है। उनके नेताओं के खिलाफ मामले बनाकर उन्हें हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के यहां छापेमारी और उसके बाद पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा की दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तारी असहनशीलता के प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री तो ममता बैनर्जी को ‘‘ओ दी दी ओ दी दी’’ करके सार्वजनिक मंच से संबोधित कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ गौतम अदानी को लेकर कोई कटाक्ष सहन नही किया जा सकता। इस मानसिकता और गिरफ्तारी के प्रसंग ने बहुत सारे पुराने संदर्भों को जिन्दा करके पुरानों की सहनशीलता और नयों की असहनशीलता को एकदम फिर से चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है।

यह सब अदानी समूह पर हिन्डनवर्ग की रिपोर्ट और उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को लेकर बनी नयी जन धारणा का परिणाम माना जा रहा है। जिस राहुल गांधी के चरित्र हनन के लिये अरबों खर्च किये गये थे आज इस यात्रा के बाद वही राहुल व्यक्तिगत स्तर पर मोदी से बड़ा नाम बन गया है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को लेकर फैलायी गयी सारी भ्रान्तियों को जड़ से उखाड़ फैंका है। समाज के हर वर्ग तक राहुल गांधी पहुंच गया है यह एक स्थापित सच्च है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अदानी समूह पर हिन्डनबर्ग की रिपोर्ट और उसके साथ बीबीसी और गार्जियन के खुलासों से समाज के हर वर्ग के सवालों के दायरे में आ गये हैं। अगली चुनावी जंग मोदी बनाम राहुल होने जा रही है। क्योंकि आज पूरे देश में कांग्रेस को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जिसकी पहचान देश के हर गांव तक हो। न चाहते हुए भी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ खड़े होना होगा। अन्यथा अपने-अपने राज्य से बाहर केन्द्र की सरकार को लेकर सबकी स्थिति दिल्ली में आम आदमी पार्टी जैसी होगी। आप लोकसभा के दोनों चुनावों में दिल्ली में कोई भी सीट क्यों नहीं जीत पायी? क्योंकि केन्द्र के लिये मोदी विकल्प थे। आज मोदी बनाम राहुल की अगली लड़ाई में क्षेत्रीय दलों के लिये यह सबसे बड़ा सवाल होगा। आज कांग्रेस को विपक्षी एकता से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व को पूरी कड़ाई के साथ सुधारना होगा या एक तरफ करना होगा।

अमृतपाल के बहाने पंजाब में फिर आतंक की आहट

गौतम चौधरी

पंजाब एक बार फिर से उबला पड़ा है। इस बार खालिस्तानी सोच को किसी अमृतपाल सिंह नामक युवक का नेतृत्व मिला है, जो लगातार प्रचार कर रहा है कि पंजाब के साथ नाइंसाफी हुई है और उसके लिए सीधा केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। अमृतपाल का यह भी तर्क है कि जब सामाजवाद, इस्लामिक राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्र पर चर्चा हो सकती है तो फिर खालिस्तान पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि पंजाब के सिख युवक अमृतपाल में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को देख रहे हैं। अमृतपाल के बारे में कोई कुछ भी कहे, कि वह अपनी बाल कटा चुका है, कि वह पक्का सिख नहीं है, कि वह किसी खास मकसद के लिए सिख युवकों का उपयोग कर रहा है लेकिन उसकी ताकत दिन व दिन बढ़ रही है। जिस प्रकार अमृतपाल को पंजाब में महत्व दिया जा रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि उसके पीछे कोई खास लॉबी काम कर रही है। हालांकि इसका पता लगाना खुफिया एजेंसियों का काम है लेकिन जिस प्रकार अमृतपाल की हैसियत बढ़ रही है और वह जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे साफ लगता है कि पंजाब की फिजाओं में बारूद की गंध है।

इसकी आशंका पहले भी व्यक्त की जा चुकी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरदार प्रकाश सिंह बादल दोनों यह कह चुके हैं कि पंजाब जैसे संवेदनशी प्रदेश की जिम्मेदारी अनुभवही व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकती है। लेकिन यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो जिसकी बहुमत होती है उसी की सरकार बनती है। हालिया विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली और उसने अपना नेता एक विदूषक को चुना। कल तक मस्खरी कर वाहवाही लुटने वाला व्यक्ति आज पंजाब का नीति निर्धारक है। ऐसे में पंजाब का वही होना था जो फिलहाल हो रहा है। पंजाब में जिस पार्टी की सरकार है उसका न तो दिल्ली में कोई जनाधार रहा है और न ही पंजाब में है। दिल्ली प्रदेश में भाजपा के असंतुष्टों ने आम आदमी पार्टी को मजबूती प्रदान की है। साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने क्षणिक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, जो कभी कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जनाधार भी दिल्ली की तरह फंतासी है। यही कारण है कि पंजाब को एक बार फिर से उग्रवाद अपने चंगुल में दबोचने का प्रयास कर रहा है।

पंजाब की समस्या के पीछे जो दिख रहा है वही नहीं है। इस समस्या पर गहराई से पड़ताल की जरूरत है। बता दें कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की कुछ आर्थिक सुधार वाली नीतियों के कारण देश के खुदरा व्यापारियों में असंतोष है। इस असंतोष का सबसे ज्यादा असर देश के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मे कश्मीर और लद्दाख आते हैं। यही कारण है कि इस पूरी पट्टी में से भाजपा केवल दो प्रांतों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पायी, बांकी के राज्यों में बुरी तरह हार चुकी है। जानकारों की मानें तो गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर कोई पटेल चेहरे को आगे कर चुनाव नहीं लड़ती तो वहां भी हार सुनिश्चित थी। हरियाणा में भी भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बतायी जा रही है।

अभी हाल के किसान अन्दोलन के पीछे भी इसी खुदरा व्यापारियों की भूमिका चिंहित की गयी है। केन्द्र सरकार के द्वारा लाये गये तीन कृषि विधेयक को भी पंजाब के व्यापारियों ने विरोध किया और सरकार के विरुद्धआन्दोलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाबी व्यापारियों ने बढ़-चढ़ कर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। इस समर्थन के दौरान वे यह भूल गये कि पंजाब की आम आदमी पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी से एकदम भिन्न है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पीछे वे लोग हैं जो कभी खालिस्तान और पृथकतावाद का समर्थन करते थे। अब जब सरकार बन गयी तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो क्षद्म पृथकतावादी समूह था, उसका चेहरा अब बेनकाब होने लगा है। पंजाब के खत्री, बनिया और बाभन एक बार फिर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अबकी बार उन्हें न तो कांग्रेस का सहयोग मिल रहा है और न ही भाजपा का। वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस अब हिन्दुओं के सहयोग की स्थिति में नहीं है। रही बात भाजपा की तो इन्होंने आम आदमी पार्टी का सहयोग किया, इसलिए अमृतपाल के मामले में केन्द्र सरकार भी कन्नी काट रही है।

पंजाब में दो प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया है। पहला कि केन्द्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करती है और दूसरा कि अमृतपाल केन्द्रीय एजेंसी का बंदा है। गौर करने पर यह दोनों नैरेटिव गलत लगता है। यदि पंजाब के साथ केन्द्र सौतेला व्यवहार करता तो पंजाब को दी जाने वाली रियायत बंद कर दी गयी होती। दूसरा, अमृतपाल केन्द्रीय एजेंसी का बंदा होता तो भला वर्तमान पंजाब पुलिस उसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? सच तो यह है कि अमृतपाल पंजाब की पृथकतावाद समर्थक शक्तियों का नया डिजाइन है। इस डिजाइन को विदेशी शक्तियों ने प्रशिक्षित किया है और वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। हां, इस मामले में केन्द्र सरकार भी कोई दूध की धुली नहीं है। वह भी अपनी रोटी सेंक रही है। उसे पता है कि कांग्रेस के पराभव के बाद पंजाब में कांग्रेसी हिन्दू उनकी ओर तभी झुकेंगे जब पूरी तरह आतंकवाद से त्रस्त होंगे। अमृतपाल के मामले में केन्द्र सरकार की ढ़ील का यह भी एक कारण हो सकता है।

मामला चाहे जो भी हो यदि इस नासूर को जल्द ठीक नहीं किया गया तो पंजाब देश के लिए कैंसर साबित होगा। यह प्रदेश फिर से आतंकवाद की गिरफ्त में होगा। हालांकि इस देश को अब तो कुछ होना जाना नहीं है लेकिन पंजाब और पंजाबियत को बहुत घाटा पहुंचेगा। इसलिए पंजाब को बंदूक की राजनीति का अखाड़ा बनने से रोकना होगा। इसे विदेशी शक्तियों से भी महफूज रखना होगा क्योंकि पंजाब इस पूरे खित्ते के लिए भविष्य का नेता है।

‘‘शैल’’ साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. **प्रकाशन स्थान**	:	शैल कार्यालय ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, लक्कड़ बाजार शिमला
2. **प्रकाशन अवधि**	:	साप्ताहिक
3. **मुद्रक का नाम**	:	**बलदेव शर्मा**
4. **राष्ट्रीयता**	:	भारतीय
5. **प्रकाशक का नाम**	:	बलदेव शर्मा
6. **पता**	:	ऋचा पिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. **सम्पादक का नाम**	:	बलदेव शर्मा
8. **उन व्यक्तियों के नाम** और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

कांगड़ा की ऑर्गेनिक ऊन की पहुंच पश्चिमी बाजारों तक

प्रदेश वूल फेडरेशन ने पशुपालकों की आर्थिकी को किया सुदृढ़

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका का अभिन्न अंग है। प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों ने कृषि के साथ-साथ भेड़ पालन को अपनाकर अपनी आमदनी में वृद्धि की है। राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के किसानों के लिए भेड़ पालन जीवनयापन का प्रमुख जरिया है।

प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा गाय और भैंस के दूध तथा गाय के गोबर इत्यादि की खरीद के लिए हाल ही में लिए गए किसान हितैषी निर्णयों में इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है। अब भेड़ पालकों को लाभान्वित करने के लिए भी विभिन्न उपायों पर कार्य किया जा रहा है।

राज्य में प्रमुख रूप से गद्दी और रामपुर बुशहरी नस्ल का पालन किया जाता है। गद्दी नस्ल की भेड़ चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जबकि रामपुर बुशहरी नस्ल किन्नौर, रामपुर और शिमला में पायी जाती है।

राज्य में वर्ष 2019 में की गई पशुधन गणना के अनुसार राज्य में कुल 7,91,345 भेड़ें हैं जिसमें विदेशी नस्ल की संख्या 72821 है और स्वदेशी नस्ल की 7,18,524 भेड़ें है।

भेड़पालक ऊन, पशु, मांस, खाद और दूध इत्यादि उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। भेड़पालकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तकनीकी और यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से भेड़ की ऊन निकालने की सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ भेड़पालकों से ऊन की खरीद के लिए 133.39 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड भी बनाया गया है। बाजार को ध्यान में रखते हुए ऊन का 125 से 150 मीट्रिक टन प्रापण किया जाता है। इसके लिए भेड़ पालकों को मौके पर भुगतान भी किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में कुल 15.50 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया जाता है, जिसके आधार पर प्रति भेड़ लगभग 1.9 किलोग्राम का उत्पादन होता है। सफेद ऊन की दर 71.50 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर 34.10 रुपये प्रति किलोग्राम और काली ऊन 45 रुपये प्रति किलोग्राम से 25.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन भेड़पालकों को भेड़ों की क्रॉस-ब्रीडिंग प्रक्रिया अपनाने और वस्त्र उद्योग की मांग के अनुसार परिधान निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन उत्पादित करने के लिए के लिए प्रेरित करती है।

हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन राज्य के भेड़ पालकों को 11 रुपये से 13 रुपये प्रति भेड़ तक की रियायती दरों पर उपकरणों द्वारा भेड़ की ऊन निकालने की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। उपकरणों के माध्यम से भेड़ की ऊन निकालने से समय की बचत होने के साथ यह पशु के स्वास्थ्य के अनुकूल भी होती है। यह सुविधा प्रशिक्षित और अनुभवी भेड़पालकों की मदद से प्रदान की जा रही है।

गुणवत्ता के लिहाज से विशिष्ट पहचान रखने वाली हिमाचली ऊन की मांग बाज़ारों में निरंतर बढ़ रही है। हिमाचली ऊन प्रदेश के विभिन्न भागों के साथ-साथ पश्चिमी बाजारों की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही है। प्रदेश के निजी हितधारक भी राज्य के कुछ हिस्सों में हिमाचली ऊन के जैविक प्रमाणन और अन्य प्रमाणन जैसे आर. डब्ल्यू.एस. (रिस्पॉन्सिबल वूल स्टैंडर्ड्स) में निवेश कर रहे हैं।

चंबा जिले के होली के गांव देओल के प्रगतिशील भेड़पालक जय सिंह ने बताया कि वह वूल फेडरेशन को लगभग 900 से 1000 किलोग्राम क्रॉसब्रीड ऊन 85.80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय करते हैं। वूलफेड की ऊन निकालने की टीमें भरमौर में उनकी भेड़ों की ऊन निकालने में मदद करती है। फेडरेशन के सहयोग से वह 800 भेड़ों के झुंड को सफलतापूर्वक पालने में सफल हुए हैं। पारम्परिक रूप से ऊन निकालने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं और वे प्रति भेड़ 25 रुपये से 30 रुपये शुल्क लेते हैं।

कांगड़ा जिले के छोटा भंगाल के भेड़ पालक मोहिंदर ठाकुर ने बताया कि वह सर्दियों में अपने लगभग 300 भेड़ों के झुंड के साथ नालागढ़ के पास रामशहर चले जाते हैं। फेडरेशन उन्हें रामशहर के पास जंगल में भेड़ की ऊन निकालने की सुविधा प्रदान करता है और नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती है। जिससे उनकी समस्याओं के निवारण के लिए स्थानीय पशु चिकित्सकों से परामर्श और प्रशासन से आवश्यक सहायता भी प्राप्त होती है।

प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप आज राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था निरंतर आगे बढ़ रही है और इससे समाज के सभी वर्गों तथा दूरदराज क्षेत्रों का समान विकास भी सुनिश्चित हो रहा है।

स्वरोजगार का उत्तम साधन है, सेब उत्पादन

शिमला। बागवानी एवं कृषि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से हिमाचल ने इस क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। विभिन्न प्रकार की कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त प्रदेश की जलवायु का भरपूर लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार इससे संबंधित सभी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है।

बागवानी एवं कृषि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से हिमाचल ने इस क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। विभिन्न प्रकार की कृषि एवं बागवानी गतिविधियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त प्रदेश की जलवायु का भरपूर लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार इससे संबंधित सभी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। सेब उत्पादन भी ऐसी ही एक गतिविधि है, जिसके लिए प्रदेश में उचित परिस्थितियां और वातावरण उपलब्ध है। राज्य सरकार इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है और प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो बागवानों को आकर्षित करने में सफल रही हैं।

सेब उत्पादन के क्षेत्र में चंबा जिले में बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है और यहां के लोग सेबों की खेती में विशेष रूचि ले रहे हैं। इससे वे स्वरोजगार लगा कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं।

चंबा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत कीड़ी का गांव पदरूही। यहीं रहते हैं प्रगतिशील, मेहनतकश और क्षेत्र के लिए अनूठी मिसाल बने बागवान धारो राम। धारो राम बताते हैं कि वह पहले पारंपरिक खेती बाड़ी का काम किया करते थे। उसके बाद सब्जी उत्पादन के साथ पॉलीहाउस का काम भी शुरू किया परंतु इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आमदनी नही हो पाती थी जिससे वे अपने परिवार का गुजर बसर सही ढंग से कर सकें। एक दिन मैंने उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुहिम के बारे में सुना । मैंने विभाग से हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में जानकारी हासिल कीस जानकारी हासिल करने के उपरान्त मैंने सेब उत्पादन में रुचि दिखवाना शुरू कर दिया।

धारो राम पिछले 5 वर्षों से उद्यान विभाग के सहयोग से हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सेब के उत्पादन से आय अर्जित कर रहे हैं। वे यह भी बताते हैं कि सेब उत्पादन से हर साल लगभग सभी खर्च निकालकर 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। सेब उत्पादन में परिवार के पालन पोषण के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सेब उत्पादन के साथ-साथ वे विभाग द्वारा पंजीकृत सेब के पौधों की नर्सरी भी चला रहे हैं। जिससे वे क्षेत्र के लोगों को अच्छी किस्म के सेब के पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं। धारो राम ने बताया कि शुरुआती दौर में सिंचाई की व्यवस्था न होने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सिचाई की समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्र में जल शक्ति विभाग द्वारा उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया गया।

योजना के अंतर्गत कलस्टर में सिंचाई के लिए 12 टैंकों का निर्माण किया गया जिससे सिंचाई की समस्या से निजात मिली ।

वे बताते हैं कि अभी मेरे पास लगभग 1500 सेब के पौधे हैं जिसमें 18 प्रजातियां है, इन्ही प्रजातियां को विभाग द्वारा पंजीकृत नर्सरी में पौधे भी तैयार कर और पौधों की बिक्री भी कर रहा हूं।

उप निदेशक उद्यान डॉ. राजीव चंद्र बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैंक के सहयोग से किसानों व बागवानों का सामूहिक तौर पर समग्र विकास करने हेतु चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य समूह के किसानों को मुफ्त सिंचाई व्यवस्था करना व उद्यानिकी के विभिन्न मदों को आधुनिक तौर पर विकासित करना है ।

जिला चंबा में 33 समूहों (क्लस्टरों) का चयन किया गया है, जिसके लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपए कार्य योजना पर हुई है। और सभी क्लस्टरों का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। जिसके अंतर्गत 1500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई व्यवस्था करने का लक्ष्य है।

इस वर्ष चंबा में 30,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसकी पहली खेप में 17 हजार पौधे वितरित किए जा रहे हैं।

धारो राम राज्य सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और सही दिशा में की गई मेहनत के सुखद परिणामों की जीती जागती मिसाल हैं। उनकी सफलता की कहानी अनेकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है और बड़ी संख्या में लोग स्वरोजगार लगाने को प्रेरित हो रहे हैं।

चंबा पारंपरिक शिल्प कलाओं की समृद्ध विरासत

शिमला। चंबा जिला में विभिन्न तरह के पारम्परिक शिल्प कलाओं की समृद्ध विरासत रही है।

चंबा रुमाल, मिनिएचर पेंटिंग, मूर्तिकला, काष्ठ कला , चंबा चप्पल, चंबा थाल से संबंधित व्यवसाय में कई कलाकार -शिल्पकार अपना जीविकोपार्जन अर्जित कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित वैरावाली माता स्वयं सहायता समूह से रीना कुमारी और रेखा देवी, नव दृष्टि स्वयं सहायता समूह से विनोद कुमार चंबा चप्पल से अपनी आजीविका को सशक्त बना रहे हैं।

इनका कहना है कि समय-समय पर हमारे स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग उपलब्ध करवाया गया है। रिवाल्विंग फंड के अतिरिक्त कम दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यह शिल्पकार अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में सक्षम हुए हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से चंबा चप्पल की पैकिंग को लेकर आकर्षक बॉक्स भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

चम्बा की समृद्ध कला एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को लेकर ज़िला प्रशासन ने पहल करते हुए चंबयाल नामक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटियों को पंजीकृत किया गया है। खास बात यह है कि ज़िला के प्रसिद्ध कला उत्पाद चंबा रुमाल, और चंबा चप्पल को जीआई अधिनियम 1999 के तहत ''जीआई'' टैग भी हासिल हो चुका है।

बैरावाली माता स्वयं सहायता समूह की सदस्य रीना बताती है कि नगर परिषद चंबा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत हमारा स्वयं सहायता समूह बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को 10 हजार रुपए का रिवाल्विंग फंड मुहैया करवाने के साथ-साथ बैंक ऋण की सुविधा भी मिली हुई है। सुविधा के तहत हाल ही में हमने 5 लाख रुपए का ऋण कम ब्याज दर पर लिया है।

उन्होंने बताया कि हमारे इस समूह में 9 सदस्य हैं और हम सभी मिलकर चंबा चप्पल का काम करते हैं। समूह द्वारा हाथ से बनाए हुए रेशम के धागों से चंबा चप्पल पर कढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि चंबा चप्पल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध है।

रीना ने बताया कि चंबा चप्पल से वे सभी सदस्य अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। चंबा चप्पल देश भर में प्रसिद्ध है और यह सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि चंबा में विभिन्न त्योहारों उत्सव, मेलों व अन्य जिला स्तरीय कार्यक्रमों में भी वे चंबा चप्पल की प्रदर्शनी लगा कर भी अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं। इसी स्वंय सहायता समूह की सदस्य रेखा भी बताती हैं कि चंबा चप्पल का कार्य कर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं।

नव दृष्टि स्वयं सहायता समूह से विनोद कुमार का कहना है कि पिछले 1 साल से सहायता समूह में काम कर रहे हैं। विभाग द्वारा हमें समय-समय पर सहयोग दिया जा रहा है। हमारे समूह को मिशन के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी लगाने का मौका भी दिया जाता है। समूह के माध्यम से हमें रिवाल्विंग फंड मुहैया कराया जा रहा है जिससे हमें काफी मदद मिल रही है। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण चंबा द्वारा हमें चंबा चप्पल की पैकिंग के लिए बॉक्स भी मुहैया करवाए गए। इस अच्छे पैकिंग बॉक्स से चंबा चप्पल की बिक्री में भी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक रुचि महाजन ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जिला चंबा में 180 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं जिसमें 10 एरिया लेवल फेडरेशन और एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन शामिल है।

बैरावाली माता स्वयं सहायता समूह जो 8 से 10 महिलाओं का समूह है जो चंबा चप्पल पर कढ़ाई लेकर अन्य उत्कृष्ट कार्य कर रही है। चंबा चप्पल पर की गई कढ़ाई यहां पर आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है इसके साथ इसे देशभर में पसंद किया जा रहा है। जब से चंबा चप्पल की बिक्री ऑनलाइन हुई है तब से इसकी बाजार में काफी मांग बढ़ी है जिससे इस पर कार्य करने वाले समूह को काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बैरावाली माता स्वयं सहायता समूह तीन बार लोन की सुविधा भी प्राप्त कर चुका है जिसमें 4 प्रतिशत दर से सब्सिडी का भी प्रावधान है। वर्तमान में इनका ऋण 5 लाख है, जिसका प्रयोग वे अपने कार्य में कर रहे हैं । साथ ही साथ संबंधित विभाग इन्हें रिवाल्विंग फंड भी मुहैया करवा रहा है, जिससे समूह को काफी हद तक लाभ प्राप्त हो रहा है।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने वित्त और केन्द्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

शिमला/शैल। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के उद्घाटन भाषण के साथ जी-20 वित्त और केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की दूसरी बैठक शुरू हुई। संबोधन के दौरान, युवा कार्यक्रम मंत्री ने कहा कि वित्त ट्रैक जी-20 प्रक्रिया के मूल में है और वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। वित्त ट्रैक में मुख्य कार्य-क्षेत्र वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिम, विकास वित्त सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल, वित्तीय समावेशन और वित्तीय क्षेत्र के अन्य मुद्दे, बुनियादी ढांचा विकास और वित्तपोषण, स्थायी वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान शामिल हैं।

G20
2nd FINANCE & CENTRAL BANK DEPUTIES MEETING
HON'BLE MINISTER

अपने उद्घाटन भाषण में ठाकुर ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के महत्व और हमारी एक पृथ्वी को बेहतर बनाने, हमारे एक परिवार के भीतर सद्भाव उत्पन्न करने और हमारे एक भविष्य की आशा प्रदान करने पर केंद्रित प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। यह विषयवस्तु वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर भारत के महत्व को दिखाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी, खाद्य व ऊर्जा असुरक्षा, बड़े पैमाने पर महंगाई, बढ़ा हुआ ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन की खराब होती स्थिति और भू-राजनीतिक तनाव के मंद प्रभावों का सामना कर रही है। इन सभी संकटों का प्रभाव विश्व की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं की प्रगति को पीछे धकेल सकता है।

ठाकुर ने कहा कि जी-20, केंद्रित संवाद व विचार-विमर्श के माध्यम से इन चुनौतियों के लिए व्यावहारिक वैश्विक समाधान तलाशने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और इसके लिए भारत की अध्यक्षता सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान करना चाहती है।

इसके अलावा ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में 2023 में जी-20 वित्त ट्रैक चर्चाओं में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना, 'भविष्य के शहरों' का वित्तपोषण करना, वित्तीय समावेशन व उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना, अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडे को आगे बढ़ाना और अन्य विषय शामिल होंगे। जी-20 के तहत विभिन्न कार्य बलों ने पहले ही इन प्रमुख मुद्दों पर कार्य शुरू कर दिया है।

प्रतिनिधियों की यह बैठक विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने के लिए समर्पित है, जिसे जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा 24 और 25 फरवरी 2023 को उनकी बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। यह विज्ञप्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर जी-20 के सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतीक है तथा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ सीधे जोड़ती है। इसमें जनसाधारण को आश्वस्त करने की क्षमता है कि प्रमुख वैश्विक समस्याओं के समन्वित समाधान पर जी-20 देशों के बीच आम सहमति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्तमान मंदी से उबरने में मदद कर सकती है तथा विकास और समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।

नीति निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि यह विश्वास बनाए रखा जाए। जी-20 ने अपनी स्थापना के बाद से, समय-समय पर संकट के समय में आम सहमति बनाने में अपनी क्षमता साबित की है। भारतीय अध्यक्षता का मानना है कि सफलता आने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों का अनुमान लगाने, रोकने और तैयार करने की हमारी क्षमता में निहित है। यह एक समावेशी और नए बहुपक्षवाद का आहवान करता है।

अपने समापन भाषण में, ठाकुर ने बहुपक्षवाद की भावना की आकांक्षा रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि विवादास्पद विषय हैं और देशों को अपनी घरेलू आकांक्षाओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। इस रचनात्मक और उपयोगी चर्चा के माध्यम से हम सामूहिक रूप से अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाएं : अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हों।

अनुराग ठाकुर धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति 'दिशा' की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना, डिजिटल भारत, प्रधानमंत्रे खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमपी लैड फंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गयी।

(दिशा)
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)
की बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है।

केंद्र सरकार ने आम बजट 2023 में केसीसी लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें खासकर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को व्यापक दृष्टि से विकसित करें, ताकि ये जल संरक्षण में उपयोगी होने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी जरिया बनें। अमृत सरोवर भू-जल स्तर में वृद्धि और सिंचाई एवं पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आसपास सुंदरीकरण करने के साथ ही उन्हें मत्स्य पालन गतिविधियों से भी जोड़ें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण के लिए पहाड़ों और घाटियों में संकरी जगहों पर छोटे बांध बनाने के विकल्प तलाशें। इससे जल संरक्षण के साथ साथ वहां जलीय खेल गतिविधियों के अवसर भी बनेंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसे देखते हुए कांगड़ा जिले में भी मोटे अनाज के उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर बल दें। उन्होंने कहा कि जिले में स्वयं सहायता स्मूहों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ने की दिशा में काम करें। उनके उत्पादों को अच्छी मार्केट प्रदान करें। उन्होंने मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जिले में किसानी-बागवानी में अच्छे काम से मिसाल कायम करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को लोगों के सामने लाएं, ताकि अन्यों को उनसे प्रेरणा मिले। हिमाचल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफलता का एक मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर रोड मैप तैयार कर साझा करने को कहा। अनुराग ठाकुर ने जिले में खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में खनन लीज दी गई हैं, वहां उसका क्या प्रभाव रहा है, वह देखने-सझने के लिए सैटेलाइट चित्र डाटा के अध्ययन के अलावा ड्रोन सर्वे कराएं, ताकि भविष्य के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसकी स्पष्टता हो। उन्होंने अधिकारियों को जिला खनिज फाउंडेशन फंड कार्यक्रम के तहत साल 2016 से अब तक एकत्रित धनराशि और संबंधित क्षेत्रों में उसके आनुपातिक आंबटन का ब्योरा साझा करने के निर्देश दिए।

अनुराग ठाकुर ने एमपी लैड फंड का ब्योरा लेते हुए साल 2019, 20 और 21 में विकास कार्यो की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस अवधि में भूमि विवाद अथवा अन्य कारणों से जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनके लिए जारी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए ताकि उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

अनुराग ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों से जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसन सेवाओं का जायजा लेने और अगली बैठक में फीडबैक साझा करने को कहा। उन्होंने सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर गांव और पंचायत बनाने की दिशा में काम करने को कहा।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा अपने स्थान पर जूनियर अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।

बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधाायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का तथा गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सभी से एक टीम की तरह कार्य कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा हर नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने बैठक में जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन तय बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने जिले में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। हिम ईरा ब्रैंड के तले इन उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। एयरपोर्ट और होटलों में स्वयं सहायता समूहों को आउटलेट मुहैया कराने के साथ ही उपायुक्त कार्यालय परिसर में भी हिम ईरा का आउटलेट खोला गया है। इसके अलावा मिशन धन्वंतरि के तहत तुलसी, कैमोलाइन, अश्वगंधा जैसे औषधीय उत्पादों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित की जाए विश्वसनीय एवं उच्च गति युक्त संचार सुविधा:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत आयोजित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की तृतीय बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदेश के दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं सुनिश्चित उच्च गति संचार सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर कनेक्टिविटी को और सशक्त करने तथा गुणवत्तापूर्ण संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी समयबद्ध प्रयास करने को कहा।

मुख्य सचिव ने 4-जी सेचुरेशन परियोजना के तहत लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करने के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत स्वीकृतियां प्रदान करने के मामलों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने पीएम गतिशक्ति स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल के तहत अतिरिक्त डेटा लेयर के एकीकरण के लिए भी ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने लोगों को गुणवत्तापूर्ण संचार सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिगत फाइबर युक्त मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा।

उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका अहम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा से ई-शासन, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित होगी। इससे सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिकों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित हितधारकों के लिए रणनीति तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने का दायित्व राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के लक्ष्यों में निहित है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध करवाने तथा फाइबर युक्त नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन, सचिव ग्रामीण विकास प्रियातु मंडल, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी मुकेश रेपस्वाल, भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार विभाग भारत सरकार, वन विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

सेलुलर ऑपरेशन्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में देशभर में अव्वल

शिमला/शैल। इण्डिया टूडे पर्यटन सर्वेक्षण एवं पुरस्कार के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स तथा बेस्ट माउन्टेन डेस्टिनेशन्स श्रेणी में विजेता पुरस्कार प्रदान किए गए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नई दिल्ली में इण्डिया टुडे समूह द्वारा आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में केन्द्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से यह पुरस्कार प्राप्त किए।

बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन श्रेणी में रिवर राफटिंग के लिए कुल्लू, मोस्ट सीनिक रोड्स श्रेणी में शिमला-किन्नौर मार्ग तथा बेस्ट माउन्टेन डेस्टिनेशन्स श्रेणी में शिमला एवं मनाली को देश के विभिन्न राज्यों में स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण एवं इण्डिया टुडे समूह सम्पादकीय मॉडल द्वारा निर्धारित मानकों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त विजेता घोषित किया गया।

हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊर्जावन नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार अनछुए पर्यटक स्थलों के चरणबद्ध विकास पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, पारम्परिक हस्तशिल्प एवं हस्तकलाएं और आतिथ्य सत्कार की विश्वभर में विशिष्ट पहचान है। वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल की समृद्ध विरासत से पर्यटकों को रू-ब-रू करवाने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार ने इतिहास, संस्कृति एवं कला के वैज्ञानिक संवर्द्धन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांगड़ा को 'पर्यटन राजधानी' बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पर्यटन क्षेत्र के सत्त विकास में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के शिमला, कुल्लू-मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर यातायात दबाव कम करने एवं पर्यटकों को मनभावन हिमाचल में अधिक से अधिक समय तक ठहराव के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार साहसिक, धार्मिक, ग्रामीण एवं सप्ताहान्त पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। पर्यटकों को होम स्टे श्रृंखला के माध्यम से राज्य के अनछुए प्राकृतिक स्थलों पर समय बिताने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य में पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए विभिन्न अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर रही है। राज्य के पारंपरिक व्यंजनों एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक भी हिमाचल की विविध संस्कृति एवं हस्तकलाओं से लाभान्वित हो सकें।

हर्षवर्धन चौहान ने इन पुरस्कारों के माध्यम से हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मंच प्रदान करने के लिए इण्डिया टुडे समूह का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश सरकार को बल्क ड्रग पार्क ऊना के लिए मिला 225 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग से राज्य के बल्क ड्रग पार्क, ऊना के सामान्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास के लिए 225 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान (ग्रांट इन एड) की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है।

यह सहायता अनुदान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अधिसूचित बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना के योजना दिशा-निर्देशों के तहत प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन और सहायता अनुदान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बल्क ड्रग पार्क राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और इससे राज्य के फार्मा पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लगभग 8000-10,000 करोड़ रुपये के निवेश और 15,000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अपेक्षित अवसर सृजित करने की क्षमता की इस मेगा परियोजना का राज्य सरकार समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ 'हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (एच.पी.बी.डी.पी.आई.एल.) 15 फरवरी, 2023 को पंजीकृत किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बल्क ड्रग पार्क के समय पर निष्पादन एवं प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना समन्वय समिति का गठन करेगी।

उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग इस पार्क के निर्माण के लिए विद्युत और सड़क के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे की योजना पर संबंधित विभागों के साथ कार्य पहले ही पूरा कर चुका है। इस पार्क की बिजली की मांग का अनुमान लगभग 120 मेगावाट है और एपीआई इकाइयों के संचालन के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए ऊना और टाहलीवाल से दो ट्रांसमिशन लाइनों की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की पूंजी लागत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। इसके लिए बल्क ड्रग पार्क के विकास, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रणनीतिक निवेश के दृष्टिगत ट्रांजेक्शन सलाहकार के चयन के लिए निविदा की जा चुकी है। इसके अलावा, बल्क ड्रग पार्क की पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के लिए सलाहकारों के चयन की निविदा प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है।

बागवानी मंत्री ने मास्टर ट्रेनरों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी एवं मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय मामले व बागवानी मोहन लाल ब्राक्टा ने समेती मशोबरा में आयोजित एक कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों से संवाद किया और उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किए। इसमें 30 अधिकारी और 25 किसान शामिल हुए।

यह संस्थागत मास्टर ट्रेनर्ज प्रशिक्षण न्यूजीलैंड प्लांट फूड एंड रिसर्च लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विश्व बैंक वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है।

न्यूजीलैंड प्लांट फूड एंड रिसर्च लिमिटेड (एनजेड पीएफआर) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शोध संस्थान है। यह न्यूजीलैंड के उद्योगों के लिए उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों और फसलों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। एनजेड पीएफआर के विशेषज्ञ 2018 से परियोजना के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से उच्च घनत्व वाले बागीचों की स्थापना और प्रबंधन के संदर्भ में बागवानी विभाग के तकनीकी कर्मचारियों और किसानों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इन विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य उच्च और मध्यम घनत्व वाले बागीचों की स्थापना और मौजूदा बागीचों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रासंगिक सूचना उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रसार द्वारा उद्यान विभाग व किसानों की कार्यान्वयन क्षमताओं को मजबूत करना तथा सेब की उत्पादकता में सुधार करना है।

इन विशेषज्ञों ने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का दौरा किया है और वे राज्य में खेती-बाड़ी के तौर तरीकों से परिचित हैं। प्रदेश के दौरे के दौरान विशेषज्ञों ने उच्च घनत्व वाले बागीचों की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा सीडलिंग आधारित वृक्षों के प्रबंधन का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया। एनजेड पीएफआर विशेषज्ञों ने लगभग 500 तकनीकी अधिकारियों और 4000 किसानों को संस्थागत और विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया है। इसमें कैनोपी प्रबंधन, फसल प्रबंधन, वृक्ष पोषण, ट्रंक गर्डलिंग, नए बाग रोपण, सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन आदि शामिल हैं।

विभागीय अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें पहले से ही तीन दौर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये सभी अधिकारी विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे फील्ड प्रदर्शनों के दौरान सक्रिय रूप से शामिल हैं।

वर्तमान कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने बागीचों के जीर्णोद्धार, कवकनाशी और जैव नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण कारक, रोग जोखिम और प्रबंधन, बढ़ते गाला और फूजी, मृदा मूल्यांकन और नाइट्रेट परीक्षण स्प्रे छिड़काव और छंटाई के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा का भ्रमण भी करवाया गया। मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण से अधिकारियों और किसानों को नई और बेहतर तकनीकों के तेजी से प्रसार में मदद मिलेगी, ताकि बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकें।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1066 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना हिमाचल प्रदेश में समशीतोष्ण फलों के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास के साथ 4 घटकों जिसमें गुणात्मक फल उत्पादन, फसल के पहले और बाद के प्रबंधन, बाजार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अब तक परियोजना के 70 प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा चुका है। यह उम्मीद है कि बागवानी विकास परियोजना के सफल कार्यान्वयन के उपरांत प्रदेश के समग्र बागवानी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव पाएंगे।

न्यूजीलैंड की तकनीकी विशेषज्ञ टीम में कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. मोंतगोमरी, विशेषज्ञ डॉ. जैक ह्यूज, डॉ. माइक नेल्सन व डॉ. डेविड मैंक्टिलो शामिल हैं।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक सुरेश मोरव्टा और बागवानी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कानून व्यवस्था के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग की सार्थक पहल

शिमला/शैल। कानून व्यवस्था बनाये रखने और अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। ड्रोन, विश्लेषण तकनीक, बायोमिट्रिक सहित अनेक तकनीकों का इस्तेमाल कर नागरिकों की सुरक्षा और अपराधमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियां तकनीक का उपयोग करने में सदैव अग्रणी रही हैं। मिसाल के तौर पर वर्ष 1990 में सड़कों पर यातायात के नियमन पर नजर रखने के लिए डिजिटल कैमरों का उपयोग आरंभ किया गया था।

अब प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन एवं अन्य अपराधों पर नज़र रखने के लिए पुलिस द्वारा बॉडी वोर्न कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा शांतप्रिय राज्य है। राज्य की पुलिस सर्तक रहने के साथ-साथ नए एवं उभरते अपराधों से निपटने के लिए भी सदैव तत्पर रहती है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में मंडी नगर के लिए तीन करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इंटीग्रेटिड सर्विलैंस एंड क्राइम रिस्पांस सेंटर, व्योमनेत्र का लोकार्पण किया। यह सेंटर किसी भी आपातकालीन स्थिति में बेहतर संचार और निगरानी के साथ आपदा की प्रतिक्रिया की क्षमता में बढ़ोतरी करेगा।

बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करने के लिए मंडी शहर के सभी आने-जाने वाले मुख्य स्थलों पर अत्याधुनिक तकनीक युक्त 250 कैमरे स्थापित किए गए हैं। व्योमनेत्र चोरी, अपराध नियंत्रण जैसे संदिग्ध मामलों में निगरानी करने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह प्रणाली सुंदरनगर में स्थापित इंटैलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ क्लाउड आधारित तकनीक के साथ एकीकृत की गयी है जिससे मंडी शहर की यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।

प्रदेश सरकार व्योमनेत्र को ड्रोन के माध्यम से निगरानी और अन्य तकनीक से भी जोड़ने की योजना बना रही है। यह न केवल यातायात प्रबन्धन में सहायक सिद्ध होगा बल्कि अपराधों पर भी नजर रखी जा सकेगी। व्योमनेत्र दुर्घटना एवं आपदा जैसी आपातकालीन स्थिति में सहायक सिद्ध होने के साथ-साथ त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित

शिमला/शैल। शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने प्रदेश में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा सभी बच्चों के लिए समावेशी, समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रदेश सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सभी उचित कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें भरना सुनिश्चित करें और इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने कोविड महामारी के कारण एक या दोनों अभिभावकों खो चुके बच्चों की निजी स्कूलों में शैक्षणिक फीस माफ करने बारे वस्तुस्थिति की जानकारी भी ली।

उन्होंने विद्यालयों को स्कूल संबंधी विभिन्न समितियों जैसे पीटीए, नशे के विरुद्ध समिति, सड़क सुरक्षा, शिकायत निवारण और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठों की नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करने, विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के साथ मिलकर युवा शक्ति को नशे से बचाने के लिए नवीन पहल सुनिश्चित करें। युवाओं और विद्यार्थियों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को कम करने के लिए स्कूल प्रभावशाली नवोन्मेषी रणनीति बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित वीडियो दिखाए जाएं। उन्होंने बच्चों को नशे से बचने के लिए प्रतिज्ञा करवाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा घनश्याम शर्मा, विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

शिवधाम परियोजना में बजट का होना न होना बना विवाद

क्या शिवधाम के लिये हैरिटेज पर्यटन से हुआ पैसा डाइवरट
चर्च रिपेयर जैसे कई कामों पर नहीं हुआ कोई भी खर्च
वितीय अनियमितता पर प्रशासन का मौन सवालों में

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह जिला मुख्यालय मण्डी में निर्माणाधीन चल रही शिवधाम परियोजना का काम दिसम्बर में सत्ता परिवर्तन होने के बाद बन्द हो गया है। काम कर रहा ठेकेदार काम छोड़कर चला गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि काम बन्द होने का कारण इस परियोजना के लिये कोई बजट प्रावधान ही न होना कहा जा रहा है। बजट प्रावधान न होने की बात मुख्य मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने शिवरात्रि के उपलक्ष में आयोजित एक आयोजन में सार्वजनिक मंच से कही है। मुख्यमंत्री के इस एक आक्षेप का जवाब देते हुए इस शिवरात्रि के आयोजन के सार्वजनिक मंच से जयराम ठाकुर ने सुक्खू को राय दी है कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिये और साथ ही यह कहा है कि शिवधाम के लिये 50 करोड़ का बजट रखा गया था। ऐसे में यह रोचक स्थिति बन गयी है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। स्वभाविक है कि दोनों ही के पास प्रशासन से आयी जानकारी रही होगी। जयराम से अभी दिसम्बर में ही सता हाथ से निकली है। जो अधिकारी उस समय तक बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त काम कर रहा था वही अधिकारी आज सुक्खू सुशासन में चौथे स्थान से पहले स्थान मुख्य सचिव पर विराजमान है। दो शीर्ष नेताओं में बजट प्रावधान को लेकर वाक्युद्ध शुरू हो गया है और शीर्ष प्रशासन मौन रह कर तमाशा देख रहा है। जबकि बजट प्रावधान होने या ना होने का आरोप शीर्ष प्रशासन पर भी एक बड़ा आरोप हो जाता है। बजट प्रावधान होने न होने से हटकर भी एक बड़ा सच यह है कि परियोजना के लिये जो पहला टैण्डर जारी हुआ था उसकी टैण्डर वैल्यू 40 करोड़ थी और उस पर ई.एम.डी 20,000 मांगी गयी है जो न्यूनतम 80 लाख बनती थी। यह टैन्डर केवल सलाहकार की नियुक्ति के लिये जारी किया गया था। ऐसे में टैण्डर दस्तावेज के मुताबिक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जब यह मामला शैल में प्रकाशित हुआ था तब उसमें पर्यटन की ओर से जो जवाब जारी किया गया था उसने स्वीकार किया गया है कि इस टैण्डर की प्रक्रिया 10-12-2019 से 16-5-2020 तक पूरी कर ली गयी थी। सलाहकार की नियुक्ति के लिये कोई संशोधन जारी तक नही किया गया था। इसमें संशोधन 12-11-2020 को पहली बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया गया था। यह पत्र भी पाठकों के सामने रखा जा रहा है। विजिलैन्स ने इन्ही दस्तावेजों का संज्ञान लेकर पर्यटन निगम को कारवाई के लिये पत्र लिखा था जिस पर आज तक कुछ नही हुआ है। निश्चित है कि यदि सुक्खू सरकार ईमानदारी से इस मामले की जांच करवाती है तो बजट प्रावधान का सच भी सामने आ जायेगा क्योंकि परियोजनाओं पर खर्च तो करोड़ों का हुआ और खर्च तब हुआ है जब कहीं से पैसे का प्रबन्ध किया होगा। पैसे के प्रबन्ध के लिये यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हैरिटेज पर्यटन के लिये जो एशियन विकास बैंक से 256.99 करोड़ का ऋण लिया गया था उसके कुछ पैसे को इस काम में लगाया होगा। इसमें हैरिटेज पर्यटन के नाम पर मण्डी के ऐतिहासिक भवन का सर्वेक्षण भी शामिल है। शिमला में इसी में से 17.50 करोड़ चर्चो की रिपेयर के लिए रखा गया था। 10-09-2014 को चर्च कमेटी के साथ कॉन्टरैक्ट भी साइन हो गया था। लेकिन व्यवहार में इन चर्चों की रिपेयर के नाम पर एक पैसा भी सर्व नही हुआ। चर्चा है कि रिपेयर के लिये रखा पैसा ए.डी.बी. कीअनुमति के बिना ही कहीं और खर्च कर दिया गया है। इस हैरिटेज पर्यटन के माध्यम से बिलासपुर में मार्कंडेण्य, श्री नैना देवी, ऊना मे चिंन्तपूणी, हरोली, कांगड़ा मे पौंग डैम, रनसेर कारु टापू, नगरोटा सूरियां, धनेटा, ब्रजेश्वरी, चामुण्डा, जवालामुखी, धर्मशाला, मकलोडगंज, मसरूर, नगरोटा बगवां, कुल्लू मनाली के आर्ट एण्ड क्राफ्ट केन्द्र, बड़ाग्रां चम्बा में हैरिटेज सर्किट, मण्डी के ऐतिहासिक भवन शिमला में दालदेहरा, का ईको पार्क, रामपुर बुशैहर तथा आस पास के मन्दिर आदि शामिल थे। पर्यटन हैरिटेज के लिये एक निदेशक और आठ सलाहकार नियुक्त किये गये थे। उन्हें एक वर्ष में 4,29,21,353 रूपये दिये गये हैं। लेकिन इन चिन्हित साईटस में से किस पर कितना खर्च हुआ है यह आज तक सामने नहीं आया है। यह कार्य 2017 तक पूरे होने थे। लेकिन कितने हुए कितने रहे यह भी सामने नहीं आया है। ए.डी.बी. ने कुछ नियुक्तियों पर अप्रसन्नता भी जाहिर की थी। माना जाता है कि ए.डी.बी.का यह पैसा डाईवर्ट हुआ है जो अलग से जांच का विषय बनता है। आज जयराम के जवाब के बाद मुख्यमंत्री के लिये यह अनिवार्य हो जाता है कि वह शिवधाम परियोजना पर एक विस्तृत जांच आदेशित करें और यह सामने लाये की सही में इस योजना के लिये अपना कोई बजट प्रावधान नहीं था और न ही यह हैरिटेज पर्यटन का कोई हिस्सा था।

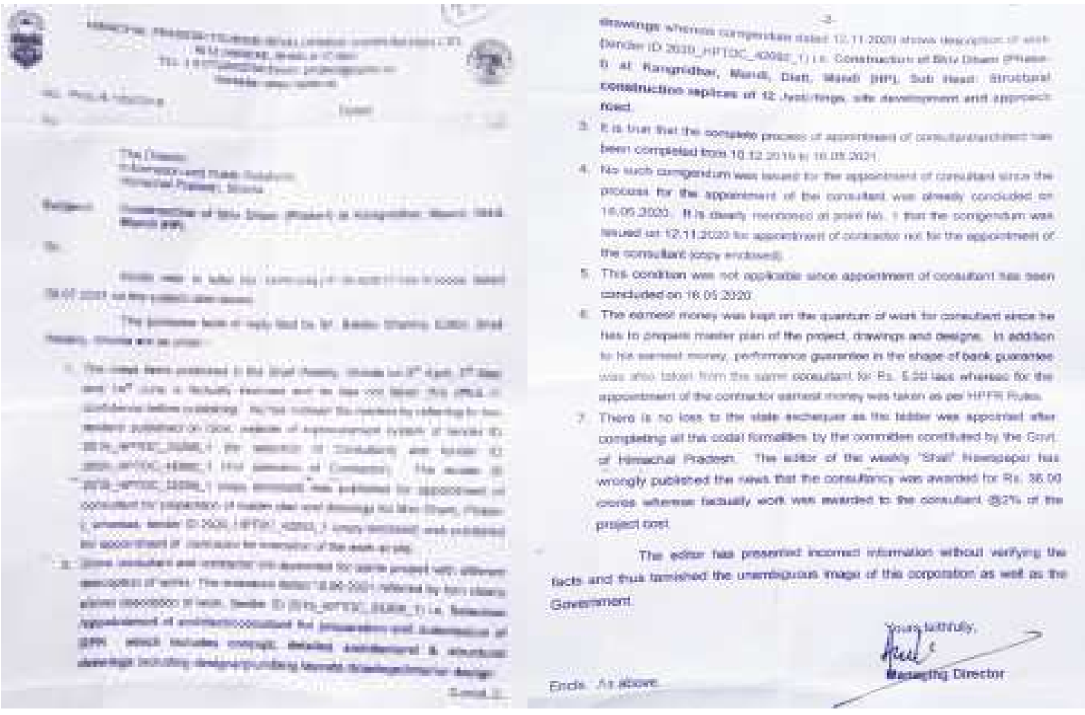

क्या अपराधियों को नौकरी देने में कोई नीति बदलाव हुआ है?

अमन काचरु के दोषीयों के रैजिडैण्ट डॉक्टर बनने पर उठी चर्चा

शिमला/शैल। डॉ राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में घटे रैगिंग प्रकरण में अमन काचरू की मौत हो गयी थी। इस मौत के बाद चले अपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट ने डॉ.अभिनव वर्मा, डॉ.नवीन कुमार और डॉ.मुकुल शर्मा को सजा सुना दी थी। इस सजा के खिलाफ यह अपील में गये थे। उच्च न्यायालय ने इनकी अपील खारिज करते हुए 4 अप्रैल को सजा और जुर्माना लगाते हुए यह फैसला दिया था। In so far as sentence is concerned, we observe that a young medical student had died consequent upon violent and repeated slapping by the accused persons which is inhuman and is a blatant breach of human right. The victim was the only son of his parents. His life has gone for a song. The accused persons were also medical students which is considered to be a cream, but their barbarous act was a dastardly act for a youth who was none else than their college-mate. While balancing all the factors of both the sides we do feel that it is absolutely not a case of giving any benefit under the benefit of Probation of Offenders Act. However, in the totality of facts and circumstances and looking at the punishment provided for the offences for which they have been held guilty and by adopting a balanced approach to meet the ends of justice, we affirm the sentence already imposed by the learned trial court, with modification in sentence that in addition to the fine already imposed, each of the accused appellants shall also deposit compensation to the tune of `1,00,000/- each under section 357 Cr.P.C. within a month from today, failing which it shall be realized by the learned trial court as a fine. The amount so realized shall be released to the next of the kin of deceased Aman Kachroo. To the above extent, the sentence stands modified. We also feel that the life of deceased cannot be compensated in money but at the same time the accused persons should also realize that they have been sufficiently atoned for their misadventure.

56. In view of the above analysis, discussion, in substance Criminal Appeals No.519, 552, 553 of 2010 and Criminal Appeal No.17 of 2011, are dismissed and also Criminal Appeals No.48 and 80 of 2011, preferred by the State under Section 377 and 378 respectively of the Code of Criminal Procedure are also dismissed.

सामान्य नियमों के मुताबिक जब किसी को अपराधिक मामले में सजा हो जाती है तो वह सरकारी नौकरी के लिये अयोग्य हो जाता है। लेकिन यह सजा भोगने के बाद जयराम सरकार के समय 21-7-2022 को 106 डॉक्टरों को (stop gap arrangement) स्टॉप गैप अरेन्जमैन्ट के तहत नियुक्तियां दी गयी। इन नियुक्तियों में यह लोग भी शामिल थे। अब सुक्खु सरकार ने रेजिडैण्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां की हैं। इन नियुक्तियों में यह लोग भी शामिल हैं। जयराम सरकार में स्टॉप गैप प्रबन्धन में नौकरी मिल गयी और अब सुक्खू सरकार में यह रेजिडैण्ट डॉक्टर बन गये हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल सरकार ने अपराधियों को लेकर कोई नीति परिवर्तन कर लिया है? क्या इस नीति का सभी को बराबर लाभ मिलेगा? क्योंकि मौत ही हो जाने से बड़ा तो कोई अपराध नही होता। जब दोनों सरकारों में सजा के तथ्यों को नजरअन्दाज कर दिया गया है तो निश्चित रूप से नीति में बदलाव हो जाने की ही चर्चा उठेगी। यदि नीति में बदलाव नही हुआ तो क्या उस तन्त्र के खिलाफ कारवाई होगी जिसने यह चयन किया है।

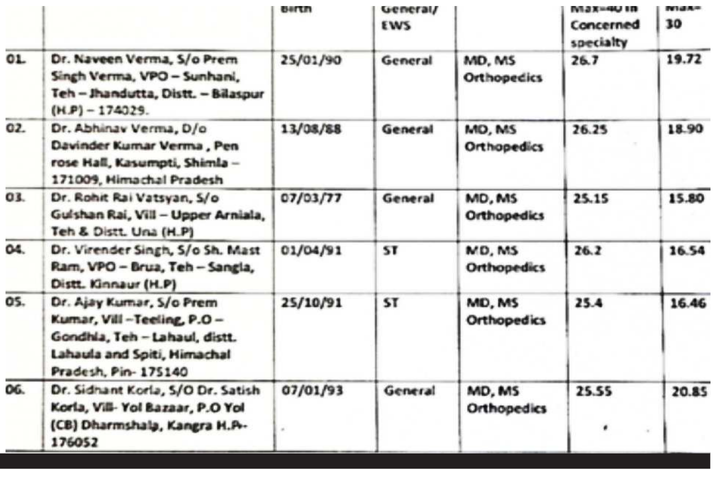

		Birth	General/ EWS		Max=40 in Concerned specialty	Max=30
01.	Dr. Naveen Verma, S/o Prem Singh Verma, VPO – Sunhani, Teh – Jhandutta, Distt. – Bilaspur (H.P) – 174029.	25/01/90	General	MD, MS Orthopedics	26.7	19.72
02.	Dr. Abhinav Verma, D/o Davinder Kumar Verma , Pen rose Hall, Kasumpti, Shimla – 171009, Himachal Pradesh	13/08/88	General	MD, MS Orthopedics	26.25	18.90
03.	Dr. Rohit Rai Vatsyan, S/o Gulshan Rai, Vill – Upper Arniala, Teh & Distt. Una (H.P)	07/03/77	General	MD, MS Orthopedics	25.15	15.80
04.	Dr. Virender Singh, S/o Sh. Mast Ram, VPO – Brua, Teh – Sangla, Distt. Kinnaur (H.P)	01/04/91	ST	MD, MS Orthopedics	26.2	16.54
05.	Dr. Ajay Kumar, S/o Prem Kumar, Vill –Teeling, P.O – Gondhla, Teh – Lahaul, distt. Lahaula and Spiti, Himachal Pradesh, Pin- 175140	25/10/91	ST	MD, MS Orthopedics	25.4	16.46
06.	Dr. Sidhant Korla, S/O Dr. Satish Korla, Vill- Yol Bazaar, P.O Yol (CB) Dharmshala, Kangra H.P- 176052	07/01/93	General	MD, MS Orthopedics	25.55	20.85